# Hkkjrh; turk ikVh
## jk"Vh; dk;dkfj.kh cBd
## 16] 17 ,o 18 flrEcj 2005
## pUub ¼rfeyukM½

## flrEcj 17] 2005

## vkfFkd iLrko

आम आदमी के हितों की रक्षा, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने, किसानों की आत्महत्या रोकने, मजदूरों का शोषण बंद करने, मध्यवर्ग की कठिनाइयों को समाप्त करने और आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करने का वादा कर यूपीए सरकार 15 माह पूर्व सत्ता में आई थी।

इन 15 महीनों में सरकार इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। एनडीए सरकार के अंतिम वर्ष में विकास दर 8.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जो यूपीए के एक साल के काल में घटकर 6.9 प्रतिशत पर आ गई।

देश में आयात में वृद्धि हो रही है और निर्यात में कमी। इस कारण इस वर्ष के पहले पांच महीनों में (अप्रैल से अगस्त) व्यापार घाटा 78300 करोड़ रूपए (17.4 बिलियन डालर) तक पहुंच गया जबकि पिछले वर्ष के इन पांच महीनों में यह 43650 करोड़ रूपए था। इस वर्ष के पहले पांच महीनों में आयात 238950 करोड़ रूपए का हुआ है जबकि पिछले वर्ष इन्हीं पांच महीनों में यह 174600 करोड़ रूपए का था।

डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार वामदलों के समर्थन पर टिकी है, इसलिए वामदलों के भयादोहन और धमकियों के आगे नतमस्तक होकर देश के हितों को तिलांजलि देने पर तुली है। कांग्रेस और वामदलों में एक बात पर वैचारिक साम्य है, वह है भाजपा विरोध। अन्य किसी भी विषय पर वैचारिक सहमति नहीं होने के कारण आर्थिक प्रगति की गाड़ी पटरी से उतर गई है। कांग्रेस ने जब भी वामदलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, देश का अहित ही हुआ है। 1971 में इन्होंने इंदिराजी के साथ मिलकर 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था, गरीबी तो हटी नहीं, देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था जरूर टूट गई। इन्हीं वामदलों की कूपमंडूक आर्थिक सोच के कारण 1991 में देश पर आर्थिक संकट गहराया था। अपनी अंतर्राष्ट्रीय देनदारियों को पूरा करने के लिए भारत को अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखना पड़ा था।

वामदल जिन बातों का केन्द्र में विरोध कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में वे उन्हीं बातों का समर्थन करते हैं। पं. बंगाल में सरकारी उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और विदेशी निवेश हो रहा है। संसद के बाहर वामदल प्रायः आर्थिक सुधारों पर सरकार की खिंचाई करते हैं, हड़ताल करते हैं, परंतु संसद के भीतर मूक रहकर सरकार का समर्थन करते हैं।

### cjkstxkjh

कांग्रेस पार्टी और वामदल रोजगार गारंटी बिल को पारित करने का श्रेय ले रहे हैं, परंतु यह बिल कांग्रेसनीत गठबंधन के चुनावी घोषणापत्र और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर खरा नहीं उतरता। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह वादा किया गया था कि शहरी बेरोजगारों तथा

मध्यम वर्ग को भी रोजगार की गारंटी दी जाएगी। परंतु सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी बिल की जगह केवल ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल पारित किया है। शहरों में रहने वाले 4 करोड़ गरीब शिक्षित बेराजगारों को इस बिल की सीमा से बाहर रखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बड़े परिवार अथवा संयुक्त परिवार में एक से अधिक वयस्क होने के बावजूद केवल एक वयस्क (स्त्री या पुरूष) को ही काम मिलेगा। उसे साल में सौ दिन 60 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से काम प्राप्त होगा। किसी बड़े परिवार या संयुक्त परिवार का भरण–पोषण केवल पांच सौ रूपए मासिक पर कैसे संभव है ?

अटलजी की सरकार की नदियों को जोड़ने, चतुर्भुज सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हवाई अड्डो–बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, देशभर में अस्पतालों व शिक्षा संस्थाओं का जाल बिछाने, व्यापक सिंचाई योजनाओं तथा विकास की कई अन्य योजनाओं से प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा हो रहा था। इन सभी योजनाओं को या तो समाप्त कर दिया गया है अथवा उन पर काम अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। उपरोक्त योजनाओं से बेरोजगारों के लिए प्रतिवर्ष उचित रोजगार उपलब्ध हो रहा था।

सरकार की गलत नीतियों से पिछले 15 महीनों में लघु व कुटीर उद्योगों के बंद होने से करोड़ों लोग बेकार हो गए हैं। यू.पी.ए. सरकार की यह घोषित इच्छा कि वे खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की मंजूरी देंगे, करोड़ों लोगों की बेरोजगारी का कारण बनेगा। वामदलों के दबाव में आर्थिक सुधार का काम अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक रोजगार पैदा नहीं हो रहे।

## df"k

देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है, परंतु यूपीए सरकार का ध्यान इस क्षेत्र पर न्यूनतम है।

देश के अनेक भाग अतिवृष्टि व बाढ़ से त्रस्त हैं, कई भागों में सूखा है। नदियों को जोड़ने व सिंचाई की योजनाओं को तिलांजलि देने के कारण कृषि क्षेत्र में स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है।

सरकार यह समझने में विफल साबित हो रही है कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से अधिक उनमें ऋण लौटाने की क्षमता पैदा करने की है। ऋण नहीं लौटा पाने की हताशा में किसान आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। फसलों का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलने तथा बाढ़, ओला, आंधी आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को भारी नुकसान पहुंचने के कारण किसान बर्बाद हो जाता है। उसकी हैसियत ऋण लौटाने की नहीं रह जाती। अनेक प्रदेशों में पिछले वर्षो के मुकाबले संप्रग सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की संख्या में वृद्धि हुई हैं हर रोज 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अकेले आंध्र प्रदेश में यूपीए के कार्यकाल में 2850 किसानों ने आत्महत्या की।

डीजल, लोहा, कृषि के औजार, बीज आदि की कीमतों में पिछले 15 महीनों में भारी वृद्धि हुई है। इन 15 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में 32 प्रतिशत और डीजल के मूल्यों में 8 रूपए की वृद्धि हुई है। उसकी तुलना में किसानों को अपनी फसल पर मिलने वाले मूल्यों में गिरावट आई है। राजग सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थो के साथ एथनोल के मिश्रण को बढ़ावा देकर किसानों को प्रोत्साहन देने के साथ पेट्रो–पदोर्थों की कीमतों को भी घटाने का प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। यू.पी.ए. सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने और उर्जा संकट को देखते हुए बायो–डीजल एक बेहतर विकल्प बन सकता हैं कई विकसित देशों में सूर्यमुखी के तेल, सोया और पाम तेल से जैविक तेल निकालने के लिए कई कार्य चल रहे है। हमारे देश में करंज, जठरोपा, नीम, महुआ से बायो डीजल निकालने की अपार संभावनाएं हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख रोजगार पैदा होने की भी संभावनाएं हैं।

## eY; of)

यद्यपि थोक मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है, किंतु एनडीए सरकार के कार्यकाल के औसत सूचकांक की तुलना में यह अभी भी अधिक है। थोक मूल्य सूचकांक आम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के मूल्य का सही सूचकांक नहीं है। जहां धनाढ्यों द्वारा उपयोग व उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई है, वहीं गरीब व मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, लोहा, सीमेंट के दाम बेहिसाब बढ़ने से सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। चीनी, फल, सब्जियों, बिजली–पानी की दरों में वृद्धि से आम आदमी की कमर टूट गई है।

पिछले 15 महीनों में कोयला, चीनी, सरसों के तेल, दाल, दूध, मिर्च, मैदा, फल, सब्जी, चप्पल आदि के दामों में 20 से 90 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। प्याज की कीमतों में वृद्धि पर दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में आई थी। अब प्याज की कीमतों में देशभर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वाजपेयी सरकार में रसोई गैस सर्वत्र सस्ती दर पर उपलब्ध थी। अब देश के अधिकांश भागों में रसोई गैस की भारी कमी है और उसमें काला बाजारी हो रही है।

भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करती है कि :–

1. शहरी बेरोजगारों के लिए संसद के अगले सत्र में एक रोजगार गारंटी बिल पारित किया जाये।
2. परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को, चाहे वह पुरूष हो या महिला, रोजगार मिलना चाहिए।
3. साठ रूपये प्रतिदिन या राज्य में दी जा रही न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो न्यूनतम मजदूरी के रूप में दी जानी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि अपर्याप्त है और आवश्यक धनराशि तुरन्त आवंटित की जानी चाहिए।
4. दो वर्षों के भीतर ग्रामीण रोजगार योजना पूरे देश के सभी जिलों में लागू की जानी चाहिए।
5. राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान बनी योजनाओं और परियोजनाओं में हो रहे कार्य में तेजी लायी जाये।
6. एनडीए सरकार ने किसानों के लिए ऋण के ब्याज की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत की थी। भविष्य में इसे और कम कर 6 प्रतिशत पर लाने का इरादा था। भाजपा कार्यसमिति सरकार से मांग करती है कि किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण की ब्याजदर और घटाते हुए उन्हें राहत प्रदान करें और कृषि को सुगम बनाए।
7. किसानों की आय बीमा योजना को देशभर में शीघ्र लागू किया जाए जिससे कि उत्पादन एवं कीमतों का बीमा सुनिश्चित हो सके।

8. एनडीए सरकार द्वारा ग्रामीण गोदामों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की महत्वपूर्ण योजना को यूपीए सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भाजपा मांग करती है कि इस योजना को तुरंत लागू किया जाए।

9. सरकार किसानों को उनकी फसल का लाभप्रद मूल्य दिलाना सुनिश्चित करे और यह तय करे कि संकट व तंगहाली में किसानों को अपनी फसल सस्ती दरों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े।

10. भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ और सूखे की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार का आह्वान करती है कि वे पर्याप्त राहत और सहायता राज्येां को दें जिससे पीड़ितों की सहायता हो सके।

11. सरकार बायो–डीजल के लिए करंज, जठरोपा, नीम, महुआ आदि के पौधारोपण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाए। इस दिशा में कार्यबल शीघ्र गठित की जाए।

12. केन्द्र सरकार बागवानी और फूलों की खेती की विपणन सहायता के लिए एक योजना बनाए।

13. खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

14. लघु एवं कुटीर उद्योगों की ऊंचा रोजगार क्षमताओं को देखते हुए ब्याज दर पर सब्सिडी दी जानी चाहिए।

15. असंगठित क्षेत्रों में राजग सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को, जिन्हें यू.पी.ए. सरकार ने समाप्त कर दिया है उन्हें पुनः प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

16. यू.पी.ए. सरकार अनिवार्य रूप से एथनाल मिश्रण को प्रारम्भ करे।

17. पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाए। अन्य अधिकांश देशों की तुलना में यह वृद्धि पहले ही अधिक है। सरकार पेट्रो पदार्थों पर उत्पादन शुल्क, आयात शुल्क कम करके इनकी कीमतें संतुलित रखे। सरकार को ऐसा सहायक उपक्रम विकसित करना होगा जिससे पेट्रोलियम पदार्थों में आए असामान्य एवं अप्राकृतिक कीमतों के उछाल को संभाला जा सकें।

18. आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं के प्रदाताओं पर लगाए गए भारी सेवा कर कर बोझ आम आदमी पर पड़ रहा हैं भाजपा की मांग है कि आम आदमी पर बोझ बन रहे सेवाकर को सरकार कम करे और अन्य में यथासंभव कम करें।

19. वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं को आयकर में मिलने वाली छूट पहले से कम कर दी गई हैं वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं को आयकर में ढाई लाख रूपए तक छूट दी जाए।

20. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के कारण जहां नियोक्ताओं, मालिकों को हानि हुई है, वहीं कर्मचारियों को भी अनेक सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। भाजपा मांग करती है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को समाप्त किया जाए।

**********************